दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार, 07 अप्रैल 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 188

महत्वपूर्ण एवं खास

100 करोड़ की वसूली मामले में अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई ने हिरासत में लिया

मुंबई (आरएनएस)। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। सीबीआई की टीम रिमांड के लिए उन्हें स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया गया। इससे पहले अनिल देशमुख ने इससे बचने के लिए विशेष अदालत की अनुमति को बंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई होनी बाकी है। विशेष अदालत के फैसले में सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में देशमुख को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी। देशमुख ने सोमवार को अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल अपनी याचिका में सीबीआई हिरासत की मांग करने वाली याचिका को भी चुनौती दी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता की याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 31 मार्च को सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन को अनुमति दी थी तथा एजेंसी को देशमुख और तीन अन्य -संजीव पलांदे, कुंदन शिंदे (देशमुख के पूर्व सहयोगी) और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।

अदरक से भरे ट्रक से 3 क्विंटल गांजा बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार

गोपालगंज (आरएनएस)। बिहार के गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गांजा (एक प्रकार का मादक पदार्थ) तस्करों के खिलाफ बड़ी कारवाई करते हुए तीन क्विंटल गांजा बरामद किया है। बरामद गांजा नागालैंड से ट्रक में लदे अदरक के साथ छिपाकर रखा गया था। इस मामले में ट्रक के साथ दो ट्रैक्टर, तीन बाइक और 20 क्विंटल अदरक भी जब्त किया गया है। पुलिस ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि जादोपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल के पास मंगलवार की रात गांजा की बड़ी खेप की आपूर्ति की जानी है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगलवार की रात उक्त जगह पर छापेमारी की, जहां से तीन क्विंटल गांजा बरामद किया गया। नागालैंड के रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रक में भरे अदरक के बीच छिपाकर गांजा जादोपुर थाने के मंगलपुर पुल के पास लाया गया था और यहां से तस्करों ने नाव से गांजा को अलग-अलग जगहों पर भेजने के लिए योजना बनाई थी। पुलिस ने छापेमारी कर ट्रक को जब्त कर लिया। गोपालगंज (सदर) के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) संजीव कुमार ने बताया कि ट्रक के साथ दो ट्रैक्टर, तीन बाइक और 20 क्विंटल अदरक जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान वैशाली जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी मनोज राय के रूप में की गई है। बरामद गांजे की कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांजा तस्करी के रैकेट से तस्करों के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। तस्करों को पकडऩे के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है।

अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ

नई दिल्ली (आरएनएस)। अमरनाथ यात्रा कोरोना महामारी के चलते पिछले दो साल से बाधित बाबा बर्फानी की यह यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू होगी। कोरोना महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा पिछले दो साल से बाधित थी। लेकिन अब सरकार के निर्देश पर अमरनाथ यात्रा आगामी 30 जून से शुरू होने जा रही है। श्राइन बोर्ड के अनुसार, 11 अप्रैल से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। बोर्ड का कहना है कि एक दिन में 20 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। यही नहीं बोर्ड द्वारा निर्धारित काउंटरों के जरिए ही बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। गौरतलब है कि सरकारी निर्देशों के मुताबिक, 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और 13 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए अमरनाथ यात्रा की अनुमति नहीं है। यही नहीं डेढ़ माह से अधिक गर्भवती महिला भी अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकती है।

भारत का कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा

नई दिल्ली (आरएनएस)। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद (समुद्री तथा कृषि उत्पाद सहित) का निर्यात 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। यह अब तक का सबसे अधिक कृषि उत्पाद निर्यात है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 19.92 प्रतिशत बढ़कर 50.21 बिलियन डॉलर हो गया। यह वृद्धि दर शानदार है और 2020-21 के 17.66 प्रतिशत यानी 41.87 बिलियन से अधिक है। यह वृद्धि उच्च भाड़ा दरों, कंटेनर की कमी जैसी अप्रत्याशित लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद हुई है। पिछले दो वर्षों की यह उपलब्धि किसानों की आय में सुधार के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में काफी अधिक सफल होगी।

चावल (9.65 बिलियन डॉलर), गेहूं (2.19 बिलियन डॉलर), चीनी (4.6 बिलियन डॉलर) तथा अन्य अनाजों (1.08 बिलियन डॉलर) के लिए यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। गेहूं निर्यात में अप्रत्याशित 273 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां 2020-21 में गेहूं निर्यात 568 मिलियन डॉलर का था वहीं यह 2021-22 में चार गुना बढ़कर 2119 मिलियन डॉलर हो गया। इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसानों को लाभ हुआ है। भारत ने चावल के लिए विश्व बाजार में लगभग 50 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात अब तक का सबसे अधिक 7.71 बिलियन डॉलर हुआ है इससे तटीय राज्य पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किसानों को लाभ मिला है। मसालों का निर्यात लगातार दूसरे वर्ष बढ़कर 4 बिलियन डॉलर का हो गया है। आपूर्ति बाधा के बावजूद कॉफी का निर्यात पहली बार 1 बिलियन डॉलर को पार कर गया है जिससे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी उत्पादकों की प्राप्ति बढ़ी है।

यह उपलब्धि वाणिज्य विभाग और एपीईडीए, एमपीईडीए जैसी उसकी निर्यात संवर्धन एजेंसियों और विभिन्न जिन्स बोर्डों के निरंतर प्रयास का परिणाम है। विभाग ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने में राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों को शामिल करने का विशेष प्रयास किया है। निर्यात से किसानों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने सीधे किसानों तथा एफपीओ को निर्यात मार्केट लिंकेज प्रदान करने के विशेष प्रयास किए हैं। किसानों, एफपीओ/एफपीसी, सहकारी समितियों को निर्यातकों से बातचीत का प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल बनाया गया है। इन कदमों का परिणाम यह हुआ है कि अब तक अज्ञात क्षेत्रों से भी कृषि निर्यात हो रहा है। वाराणसी (ताजा सब्जियां, आम), अनंतपुर (केला), नागपुर (संतरा), लखनऊ (आम), थेनी (केला), सोलापुर (अनार), कृष्णा तथा चित्तूर (आम) जैसे क्लस्टरों से निर्यात किए गए है। गैर-परम्परागत क्षेत्रों से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 'हैप्पी बनाना' ट्रेन की पहल की गई है। रीफर कंटेनरों के साथ यह विशेष ट्रेन अनंतपुर से केला जेएनपीटी, मुंबई भेजने के लिए है।

2020 की पहली तिमाही के दौरान कोविड-19 फैलने के कारण खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि हुई। इस वृद्धि ने कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान किया। राज्य तथा जिला स्तरों पर पहले से बने हुए संस्थागत ढांचों तथा महामारी से उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के विशेष प्रयासों के कारण भारत ने स्वयं को साबित किया और खाद्य सामग्री के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। रूस-यूक्रेन युद्ध के हाल के संकट के बावजूद विश्व गेहूं तथा अन्य अनाजों की सप्लाई के लिए भारत की ओर देख रहा है।

वाणिज्य विभाग कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अपने प्रयास को जारी रखे हुए है और पिछले दो वर्षों की गति को बनाए रखा गया है और आने वाले वर्षों में कृषि निर्यात नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

कोरोना वायरस के नए एक्सई वैरिएंट ने भारत में दी दस्तक, मुंबई में मिला पहला मामला

मुंबई (आरएनएस)। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट एक्सई ने भारत में भी दस्तक दे दी है। इसके संक्रमण का पहला केस बुधवार को मुंबई में दर्ज किया गया है। कुल 376 सैंपल लिए गए थे, जिनकी जांच में एक मरीज में कोरोना के एक्सई वैरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई। इस वैरिएंट की शुरुआत युनाइटेड किंगडम से हुई थी। बीएमसी ने अपने ताजा सीरो सर्वे में बताया है कि शहर में एक्सई वैरिएंट और कप्पा वैरिएंट के एक-एक मामले की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 230 लोगों की रिपोर्ट सीरो सर्वे के लिए भेजी गई थी। इनमें से 21 लोगों को अस्पातल में एडमिट कराया गया है। किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन या फिर गहन निगरानी की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सई वैरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यह ओमिक्रॉन वैरिएंट के दो स्ट्रेन्स क्न्र.1 और क्न्र.2 को मिलाकर बना है। इसका पहला केस ब्रिटेन में पाया गया था और इसे ड्गश्च वैरिएंट नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जताई है कि यह वैरिएंट सबसे तेजी से फैलने वाला साबित हो सकता है। भारत में कोरोना केसों में लगातार कमी देखी जा रही है और एक्टिव मामलों की संख्या तेजी से कम होते हुए 15 हजार से कम रह गई है। ऐसे में अब एक्सई वैरिएंट का पाया जाना चिंताएं बढ़ाने वाला है। इससे अब तक मिली सफलता पर पानी फिरने का भी खतरा पैदा हो गया है। गौरतलब है कि चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एक बार फिर से कोरोना सिर उठा रहा है। चीन की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई में लॉकडाउन की स्थिति है और एक दिन में लाखों टेस्ट किए जा रहे हैं। आईआईटी कानपुर के अनुमान के मुताबिक भारत में भी जून, 2022 तक कोरोना संक्रमण की चौथी लहर दस्तक दे सकती है।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर- भारत ने शांति का पक्ष चुना है

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के बूचा शहर में हुई हत्याओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस घटना की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। विरोधी दलों के सांसदों द्वारा लड़ाई पर भारत सरकार के स्टैंड को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने शांति का पक्ष चुना है।

नियम 193 के तहत लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जहां तक रूस-यूक्रेन लड़ाई का प्रश्न है, भारत इस लड़ाई के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का स्पष्ट मानना है कि लड़ाई से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बातचीत और शांति से ही विवादित मुद्दों का समाधान हो सकता है।

चर्चा के दौरान कई सांसदों द्वारा यूक्रेन के बूचा शहर में हुई हत्याओं के मुद्दे को उठाने का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हम बूचा में हुई हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं, यह एक बहुत ही गंभीर मसला है। हमारा मानना है कि इस घटना की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन के नोटिस पर मंगलवार को नियम 193 के तहत लोकसभा में यूक्रेन मसले पर चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने भारत सरकार के एडवाइजरी जारी करने में देरी, ऑपेरशन गंगा और यूक्रेन-रूस लड़ाई में भारत सरकार के स्टैंड को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे।

मंगलवार को ही चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए चार केंद्रीय मंत्रियों- हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने विरोधी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर निशाना भी साधा था।

बुधवार को लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने लड़ाई पर भारत के रुख को साफ करते हुए यह दावा किया कि इतने बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम किसी अन्य देश ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रभाव और रूस एवं यूक्रेन सहित अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत करने से ही यह संभव हो पाया। उन्होंने यूक्रेन से लाए गए भारतीयों छात्रों की शिक्षा और एजुकेशन लोन सहित हर मुद्दे पर उनके हितों का ध्यान रखने का वादा करते हुए कहा कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

कैलाश मानसरोवर सडक़ के लिए 650 करोड़ रुपये मंजूर करेगा केंद्र, जल्द पूरा होगा उत्तराखंड से यात्रा करने का सपना

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेपाल या चीन के बजाय उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही 650 करोड़ रुपये से अधिक की सडक़ परियोजान को मंजूरी देगा।

केंद्र सरकार भारत-चीन सीमा संपर्क सडक़ के अंतिम खंड के लिए काम शुरू करने के लिए तैयार है जो कैलाश मानसरोवर को जोडऩे की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तराखंड से यह लिंक रोड वाहनों को तीर्थ स्थल से सिर्फ 75 किमी दूर तक ड्राइव करने की अनुमति देगा।

सरकार परियोजना पर काम में तेजी लाने के लिए लगी हुई है। केंद्र मशीनीकृत निर्माण लाने के लिए एलएंडटी से लेकर टाटा समूह की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनियों और ठेकेदारों को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पहले ही शीर्ष फर्मों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम पूरा कर लिया गया है।

सीमा सडक़ संगठन (बीआरओ) ने अस्कोट से भारत-चीन सीमा तक पूरे 150 किलोमीटर लिंक का रोड फॉर्मेशन पूरा कर लिया है। रोड फॉर्मेशन में भौगोलिक और भूभाग की चुनौतियों के अलावा उसकी शेप को तय करना शामिल है जिस पर सडक़ बनेगी। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को बीआरओ ने दुर्गम हिमालयी इलाके में सफलतापूर्वक पूरा किया। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अस्कोट से सीमा तक की आखिरी 80 किलोमीटर सडक़ को पक्का करने के लिए फंड मंजूर करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, इस मामले में सबसे कठिन हिस्सा रोड फॉर्मेशन था। अब रोड फॉर्मेशन के साथ, रोड बनना शुरू हो जाएगा। केंद्र द्वारा जल्द ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। हम पूरे दो लेन सडक़ राजमार्ग को 2-3 साल के भीतर पूरा करने की उम्मीद करते हैं।

एक बार पूरी सडक़ बन जाने के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भारत चीन सीमा तक 5-6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि वहां से साइट पर पहुंचने में करीब दो घंटे का समय लगेगा। वर्तमान में दो से तीन हफ्ते में कैलाश मानसरोवर पहुंच सकते हैं। अभी के मार्ग सिक्किम या नेपाल के माध्यम से हैं।

ईडी व अन्य जांच एजेंसियों के खिलाफ संसद परिसर में शिवसेना सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली (आरएनएस)। शिवसेना सांसदों ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। दरअसल ईडी ने संजय राउत के परिवार प्रवीण राउत, वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर की 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्ककर ली है जिसमें संजय राउत की पत्नी का दादर और अलीबाग स्थित फ्लैट भी शामिल है। ईडी ने यह कार्रवाई पात्रा चॉल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में की है। इसके विरोध में बुधवार को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास तख्ती लेकर शिवसेना सांसदों ने प्रदर्शन किया और कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबने खोया जनता का विश्वास।

इससे पहले ईडी की इस कार्रवाई से भडक़े संजय राउत ने मंगलवार को कहा, क्या मैं विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी या अंबानी-अदानी हूं? चाहे हमारी प्रोपर्टी जब्त हो, गोली मारो या जेल भेजो, हम नहीं डरेंगे। 2 साल से चुप बैठाने की कोशिश है, चुप बैठा क्या? जिसको फुदकना है, नाचना है नाचने दो। आगे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई तब शुरू हुई जब लोगों ने उन पर महाराष्ट्र सरकार गिराने का दबाव बनाया।

शेखावत ने 564 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की प्रगति का किया निरीक्षण

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 564 एमएलडी क्षमता के ओखला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। यमुना कार्य योजना-श्री के अंतर्गत इस ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री सबसे पहले आईटीओ स्थित छठ घाट गए और वहां से नाव से 12 किलोमीटर दूर ओखला वोट क्लब पहुंचे। फिर शेखावत सडक़ मार्ग से ओखला एसटीपी स्थल पहुंचे। गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक जी. अशोक कुमार भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे। लागत साझा करने की व्यवस्था के अनुसार 85 प्रतिशत लागत का वहन नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार को और 15 प्रतिशत लागत वहन राज्य सरकार को करना है। ओखला एसटीपी परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 665.78 करोड़ रुपये है।

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिल्ली में स्थिति पर विचार करते हुए और दिसंबर, 2022 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एसटीपी कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2022 के बाद दिल्ली की यमुना नदी में निश्चित रूप से जल की गुणवत्ता में सुधार महसूस किया जाएगा। ओखला एसटीपी एशिया में सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। 564 एमएलडी के इस प्लांट के निर्माण के बाद यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। यह एकीकृत परियोजना है इसलिए इसके कार्य के दायरे में गाद प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। इसके अनुसार पर्यावरण संबंधी विषयों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से गाद का उचित निपटान किया जाएगा।

वर्तमान में दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 1268 एमएलडी गंदा जल शोधन के लिए कुल 11 परियोजनाएं 2009 करोड़ रुपये की लागत से एनएमसीजी द्वारा यमुना नदी संरक्षण के लिए शुरू की गई हैं। इन परियोनजाओं का उद्देश्य कोरोनोशन पिलर (कोरोनोशन पिलर एसटीपी पूर्ण) कोंडली-ओखला तथा रिठाला के जलग्रहण क्षेत्र में 1268 एमएलडी की कुल शोधन क्षमता का सृजन करना है। इन परियोजनाओं को दिसंबर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ओखला सीवेज ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स में छह अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र फेस-I (136 एमएलडी), फेस- II (55 एमएलडी), फेस- III (205 एमएलडी), फेस- IV (168 एमएलडी), फेस- V (73 एमएलडी) और फेस -VI (136 एमएलडी) हैं. फेस- I, II, III और IV संयंत्रों का निर्माण वर्ष 1993 से पहले किया गया था, जो काफी पुराने हैं. इसलिए इन्हें अपग्रेड कर उच्च मानकों के अनुरूप 564 एमएलडी की क्षमता का एक नया एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है. एसटीपी में अपशिष्ट, स्काडा, बायोगैस से बिजली उत्पादन और कीचड़ प्रबंधन आदि के गुणवत्ता मानकों की ऑनलाइन निगरानी का प्रावधान होगा.